The abovp decision, has been. impJemented and all the retirea employees, of NTRTAK opting for GPF-cum-Pension Scheme are getting pensionary benefits.

मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या

6717. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ धनराशि आबंटित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार दो प्रमुख रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही हैं, यथा (1) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), और (2) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.)

आई.आर.डी.पी. का जो एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना हैं ताकि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में समर्थ बनाया जा सके । इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में किया जाता है।

जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.आई.)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के सभी जिलों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अर्द्ध-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सभी ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अक्तूबर, 1993 से रोजगार आश्वासन योजना (इ.ए.एस.) शुरू की है जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के काम चाहने वाले व्यक्तियों को कृषि अवधि के बाद मंदी के दौरान 100 दिनों का आश्वस्त रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 297 ब्लॉकों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना में पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित धनराशि आबंटित की गई है :—

वर्ष	आबंटन (रु० लाख में)
1992–93	6472.00
1993–94	10664.00
1994–95	10573.00

2. जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को आबंटित संसाधन इस प्रकार है :—

वर्ष	आबंटित धनराशि (लाख रु० में) (केन्द्रीय+राज्य क्षेत्र)
1992–93	31473.50
1993–94	31197.24
1994–95	34339.59

SC/ST Population living in Rural areas

6718. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the percentage of SC/ST popu lation living in the rural areas with Ihe State-wise breakup from 1981 to 1991;

(b) the percentage of SC/ST population with respect of overall population living- in rural areas with state-wise breakup from 1981-1991;

(c) how much land as percentage to total cultivable land belongs to the SC/ST population with State-wise breakup from 1981-1991; and

(d) the percentage of national income that accrue^ to the SC|ST popu. lation with satewise break up during the period?

THE MINISTER OF WELFARE (SWR'I SITARAM KESRI): (a) A statement showing percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribe population in rural areas as per 1991" census is given at Annexure. Another statement showing their percentage of population in the rural as per 1991 census is given at Annexure. *[See* Appendix 173 Annexure No. 138 and 139]

(b) A statement showing the percentage of SC/ST population with respect to overall populaion living in rural areas is given at Annexure. *[See* Appendix 173 Annexure No. 140]

(c) A statement as per Agricultural Census 1980-81 is given at Annexure. Information for 1991 Census is being compiled. *[See* Appendix 173 Anne xure No. 141]

(d) As per Ministry of Planning (Dept. of Statistics), no National income estimates are prepared for SC| ST classes.

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरूपयोग

6719. श्री मूलचन्द मीणा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं धन के दुर्विनियोग के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इन संगठनों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :